RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 22 JULY TO 28 JULY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 48 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

छोटे उद्योगों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे सीबीडीटी और एमएसएमई मंत्रालय Page 3

ई-कॉमर्स कंपनियों बताना ही होगा उत्पादों का कंट्री ऑफ ओरिजिन Page 4

सिनेमा हॉल-होटल में खाने-पीने की वस्तुओं पर वसूले ज्यादा पैसे तो होगी कार्रवाई Page 7

editoria!

साइबर असुरक्षा

जैसे-जैसे साइबर संसार बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे वहां सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। समय के साथ साइबर दुनिया जरूरी होती जा रही है, लेकिन उससे जुडे भय भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और सबसे सशक्त सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट सुरक्षित नहीं हैं, तब बाकी अकाउंट्स की सुरक्षा का अनुमान मुश्किल नहीं है। इस तरह की साइबर हैकिंग से भले कोई बड़ा नुकसान हुआ न दिखता हो, पर इसने साइबर सुरक्षा व भरोसे में पहले से ही लगी सेंध को और चौड़ा तो कर ही दिया है। दरअसल, हम साइबर अपराध को अभी भी यथोचित गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में प्रति मिनट 29 लाख डॉलर का नुकसान साइबर अपराध की वजह से हो रहा है। साल 2017 के आंकडे बताते हैं कि प्रतिदिन साइबर दुनिया में करीब 7,80,000 दस्तावेज हेराफेरी या चोरी की भेंट चढ़े थे। ऐसा भी नहीं है कि साइबर सुरक्षा के काम में लगी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हों। जैसे, करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके एप्स में करीब 24,000 संदिग्ध एप्स प्रतिदिन बाधित किए जाते हैं, लेकिन ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा बराबर हैं। साल 2015 में तीन ट्रिलियन डॉलर साइबर अपराध की भेंट चढ़ गए थे और साल 2021 तक यह आंकड़ा छह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। जिस तरह से साइबर दुनिया का विस्तार हो रहा है, उसी तरह से सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र का विकास करना होगा। इस साल दुनिया भर में 300 अरब से ज्यादा पासवर्ड हो जाएंगे, बढ़ती संख्या के साथ उन्हें सुरक्षित रखने की चुनौती भी बढ़ती जाएगी। आए दिन किसी सोशल अकाउंट की हैकिंग मुख्यतः पासवर्ड की चोरी की वजह से ही संभव होती है। साइबर दुनिया के शातिर चोरों को पता है कि पासवर्ड का कौन-सा ताला कैसे खुल सकता है, इसलिए उनके लिए सरल पासवर्ड का अनुमान लगाना कठिन काम नहीं है। साइबर दुनिया में 21 फीसदी से ज्यादा फाइलें असुरक्षित हैं, उन पर किसी तरह का ताला नहीं है। आश्चर्य नहीं कि कंपनियों को तीन महीने बाद किसी डाटा या फाइल की चोरी का पता चलता है। जब व्यवस्थित कंपनियों को अपना डाटा सुरक्षित रखने में जोर आ रहा है, तब आम लोग कितने असुरक्षित होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ओबामा और गेट्स जैसी हस्तियों पर हुए साइबर हमलों के बाद दुनिया को ईमानदारी से सोचना चाहिए। सुगठित सरकारों, संगठित राजनीति व राजनेताओं पर भी खतरा बढ़ चुका है। साल 2017 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का ई-मेल हैक हो गया था और ऐसा चुनाव से कुछ ही पहले हुआ था। बहुत संभव है, इसका असर फ्रांस के चुनावों पर भी पड़ा हो। बहुत-सी हमारी बातें हैं, जिन्हें साइबर अपराधी हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और दुखद चेहरा है। दुर्भाग्य से साइबर अपराधी और डाटा चोरी को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि नैतिकता का दावा करने वाली सरकारें भी अपने प्रतिस्पर्द्धियों से जुडे डाटा चुराने में गुरेज नहीं करतीं। ऐसे में, सजग सरकारों को अपने-अपने दायरे में साइबर सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। पूरी हैकिंग को कठघरे में खड़ा करने की बजाय नैतिक हैकिंग को बढ़ावा देना और अनैतिक हैकिंग पर चोट करने की जरूरत बहुत बढ़ गई है।

अमेरिका की गुफाओं में तेल जमा करेगा भारत

जानिए इनमें कैसे स्टोर होता है क्रूड ऑयल

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कम कीमतों और सप्लाई में दिक्कत से बचने के लिए भारत ने बड़ा अहम फैसला किया है। देश के भीतर तीन सामरिक ऑयल रिजर्व हैं। पहली बार भारत ने विदेश में इमर्जेंसी ऑयल रिजर्व बनाने का फैसला किया है। भारत अपना तेज अमेरिका में जमा करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। दोनों देशों के बीच सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर एमओयू साइन हो गया है। इस ऑयल रिजर्व की क्षमता कितनी होगी, अभी यह नहीं बताया गया है लेकिन माना जा रहा है भारतीय रिजर्व से ज्यादा कैपेसिटी वाला रिजर्व ही बनाया जाएगा। यह कदम अमेरिका और भारत के सामरिक रिश्तों को डिफेंस से आगे ले जाने की दिशा में उठाया गया है।

कैसे होते हैं ऑयल रिजर्व

ऑयल रिजर्व बाहर से दिखने में बड़े-बड़े धब्बों जैसे नजर आते हैं। जमीन के नीचे सुरंगों का जाल होता है और गुफाएं होती हैं जिनमें तेल भरा जाता है। इमर्जेंसी ऑयल सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड ठिकानों को ही सबसे सेफ माना जाता है। ये जमीन से दो हजार से चार हजार फीट नीचे होते हैं। इतने प्रेशर में लीक होने की संभावना न के बराबर होती है। ऊपर से हर गुफा के टॉप और बॉटम का तापमान भी अलग -अलग होता है। इनमें से तेल निकालने के लिए नीचे से पानी भरा जाता है। तेल ऊपर आ जाता है।

भारत के पास तेल जमा करने के दो विकल्प

अमेरिका में तेल स्टोर करने को लेकर भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला कि जब तेल के दाम कम हों तब कच?चे तेल वाली गुफाओं को लीज पर लिया जाए। दूसरा ये कि लीज ले ली जाए और तेल कीमत कम होने पर अलग से खरीदा जाए ताकि बाद में मुनाफा हो।

सरकार दे सकती है तेल स्टोर करने का पैसा

अमेरिका में किसका या कितना तेल स्टोर किया जाएगा, अभी इसपर बात नहीं हुई है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल का अमेरिका के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, वह तेल खरीद सकती है। नहीं तो सरकार भी तेल का पैसा दे सकती है जैसा उसने मार्च में तेल के दाम कम होने पर सामरिक रिजर्व्स को भरते समय किया था।

भारत के पास 9-10 दिन का रिजर्व तेल

कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले भारत दिनभर में साढ़े चार मिलियन बैरल तेल की खपत कर रहा था। उसके पास 38 मिलियन बैरल का रिजर्व है जो कि अभी के हिसाब से 9-10 दिन आराम से चल जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अमेरिका का है। उसके पास 714 मिलियन बैरल स्टोर करने की क्षमता है।

22 दिन का रिजर्व तैयार करने का प्लान

भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है इसलिए कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर यहां बहुत देखने को मिलता है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार संकट के लिए होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं के दौरान सप्लाई डिस्टर्ब होने पर इनका यूज किया जाता है। भारत के भीतर तीन रिजर्व- विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक) और पादुर (कर्नाटक) में स्थित हैं। इनके अलावा सरकार ने चंदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में दो और फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया है। उसके बनने के बाद भारत के पास 22 दिनों तक का ऑयल रिजर्व होगा।

कोरोना की मारः 7.4 लाख से अधिक कंपनियां बंद

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना की मार से देश में जून अंत तक कुल पंजीकृत कंपनियों की संख्या 20 लाख से ऊपर निकल गई जबकि इसमें से 7।4 लाख से अधिक कंपनियां विभिन्न कारणों से बंद हो गईं। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 जून की स्थिति के अनुसार 12।15 लाख से कुछ अधिक कंपनियां कामकाज कर रही थीं, सक्रिय थी। आमतौर पर सक्रिय कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से होता है, जो कि मंत्रालय को जरूरी दस्तावेज और सूचनायें नियमित रूप से देती रहतीं हैं।

जून 2020 में 10,954 कंपनियां पंजीकृत की गई

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम को क्रियान्वित करता है। मंत्रालय सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कानून को भी अमल में लाता है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले जून 2020 में 10,954 कंपनियां पंजीकृत की गई, जिनकी कुल प्राधिकृत पूंजी 1,318।89 करोड़ रुपये है। एक साल पहले जून में 9,619 कंपनियों का पंजीकरण हुआ था। इस साल जून में पंजीकृत कंपनियों में कारोबारी सेवाओं के तहत 3,399 कंपनियों पंजीकृत हुई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 2,360 कंपनियां, व्यापार में 1,499 कंपनियां, सामुदायिक, व्यैक्तिक और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में 1,411 कंपनियां और निर्माण के क्षेत्र में 644 कंपनियां पंजीकृत हुईं।

जून तक 20 लाख 14 हजार 969 कंपनियां पंजीकृत थी

मंत्रालय के कंपनी क्षेत्र पर जारी ताजा मासिक सूचना बुलेटिन के मुताबिक 30 जून 2020 को कुल मिलाकर 20 लाख 14 हजार 969 कंपनियां पंजीकृत थी। इनमें से 7 लाख 46 हजार 278 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। वहीं 2,242 कंपनियों को कंपनी कानून 2013 के तहत निष्क्रिय बताया गया है। इसके अलावा 6,706 कंपनियां परिसमापन की प्रक्रिया में हैं जबकि 43,770 कंपनियां का पंजीकरण रद्दे होने की प्रक्रिया में है। इसके बाद 30 जून को 12 लाख 15 हजार 973 कंपनियां पूरी तरह से सक्रिय हैं।

तेल कुओं में उपयोग के लिए नहीं करना होगा स्टील का आयात, देश में ही बनाया इस सरकारी कंपनी ने

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मुम्बई के पास बाम्बे हाई में समुद्र के बीच में स्थित ओएनजीसी के कच्चे तेल के कुओं का फोटो तो आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उसे बनाने के लिए विशेष ग्रेड के स्टेनलेस स्टील एए 32205 का आयात करना पड़ा था। अब इस तरह का कुआं बनाना पड़े तो इसके लिए विदेशों की ओर मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेलम इस्पात संयंत्र ने एए 32205 ग्रेड का हाईली करोज़न रिज़िस्टन्ट सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील को यहीं विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली है।

सेल अध्यक्ष ने बताया बड़ी सफलता

सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी का कहना है कि करोज़न रिज़िस्टन्ट स्टील के तकनीकी विकास के क्षेत्र में यह एक बड़ी सफलता है। सेल इस ग्रेड का स्टील विकसित करने वाले देश के चुनिन्दा इस्पात उत्पादकों में से एक हो गया है। अभी तक स्टेनलेस स्टील का यह ग्रेड मुख्य रूप से आयात किया जाता रहा है। यह सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बेहद मजबूत और टिकाऊ होने के साथ ही हाईली करोज़न रिज़िस्टन्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तरफ यह उठा एक मजबूत कदम है।

कई तरह की औद्योगिक मशीनरी बनाने में होता है उपयोग

इसकी हाईली करोज़न रिज़िस्टन्ट विशेषताओं के कारण, इसका उपयोग करोज़न प्रभावित क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों और निर्माण जैसे केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट (परिवहन और भंडारण, प्रेशर वेसेल्स, टैंक, पाइपिंग और हिट एक्सॉस्ट) में किया जा सकता है। तेल और गैस की खोज (प्रोसेस उपकरण, पाइप, ट्यूबिंग, समुद्री और अन्य उच्च क्लोराइड वातावरण), लुगदी और कागज उद्योग (डाइजेस्टर और ब्लीचिंग उपकरण) के लिए इसका विशेष रूप से आयात किया जाता रहा है। इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उपकरण और जैव ईंधन संयंत्र में भी इसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि, इन सभी जरूरतों के लिए में हाईली करोज़न रिज़िस्टन्ट के साथ मजबूत स्टील की आवश्यकता होती है।

बाजार में सपाट कारोबार

सेंसेक्स 37,900 के ऊपर, निफ्टी भी नहीं रख पाया तेजी बरकरार

मुंबई। एजेंसी

बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी लेकिन शुरुआती मिनटों में ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दिखनी शुरू हो गई थी। हालांकि अब बाजार रिकवर कर चुका है और लगभग सपाट है। Stock Market Update: घरेलू शेयर बाजार में आज सपाट कारोबार देखा जा रहा है। सेंसेक्स-निफ्टी में शुरुआत से ही गिरावट देखी जा रही थी लेकिन इस समय लगभग सपाट स्तरों पर कारोबार हो रहा है। हालांकि बाजार की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई थी लेकिन घरेलू शेयर बाजार इसे बरकरार नहीं रख पाया।

कैसा हो रहा है कारोबार

सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 21.40 अंक यानी 0 .056 फीसदी की गिरावट के बाद 37,908 .93 पर कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी सिर्फ 2.00 अंक यानी 0 .02 फीसदी की गिरावट के साथ 11,160.25 पर कारोबार कर रहा था।

कैसे हुई थी ट्रेडिंग की शुरुआत

बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएसई का सेंसेक्स 247 .74 अंक ऊपर और एनएसई का निफ्टी 68.95 अंक की बढ़त के साथ खुला था लेकिन शुरुआती मिनट में ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई थी। हालांकि इस समय बाजार रिकवर हो चुका है और नाममात्र की गिरावट के साथ कारोबार चल रहा है।

बाजार में कल का बंद स्तर

कल बीएसई का सेंसेक्स 511 अंक ऊपर चढ़कर 37,930 पर बंद हुआ था। इसके अलावा एनएसई का इंडेक्स निफ्टी 140 अंक ऊपर 11,162 पर बंद हुआ था।

निफ्टी का कारोबार

बुधवार को कारोबार में निफ्टी में 26 शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और 24 शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस तरह देखा जाए तो स्थिति बराबर-बराबर की बनी हुई है और इसी का असर ट्रेड में देखा जा रहा है।

बैंक निफ्टी का हाल

बैंक निफ्टी में मामूली तेजी देखी जा रही है और 48 ।95 अंक यानी 0 ।21 फीसदी की बढ़त के साथ 22,830 ।95 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग शेयरों में मिलाजुला कारोबार देखा जा रहा है।

निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयर

निफ्टी के टॉप 5 चढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, वेदांता, पावरग्रिड, एनटीपीसी और टाइटन लिमिटेड हैं। वहीं निफ्टी के पांच सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, एचयूएल और इंफोसिस हैं । इसके अलावा श्री सीमेंट में भी गिरावट है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर दो हजार रुपये के पार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने बुधवार को कामकाज के दौरान इतिहास रचते हुए दो हजार रुपए की कीमत को पार कर 2010 रुपये का रिकार्ड भाव छूआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरी तरह कर्जमुक्त होने और जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गजों के मोटा निवेश करने से शेयर छंलाग लगा रहा है। हालांकि 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम के बाद शेयर को कुछ झटका लगा था । किंतु वह इससे जल्दी ही उबर गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विश्व की पहली 50 प्रमुख कंपनियों में अपना स्थान और मजबूत किया है। बुधवार को बीएसई में कारोबार की शुरूआत मे रिलायंस का शेयर कल के 1971.85 रुपये की तुलना में 1980.05 रुपये पर खुला। दोपहर के कामकाज में शेयर 2010 रुपये तक चढ़ा। इस स्तर पर रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 12. 70 लाख करोड रुपये को छू गया। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस का शेयर मार्च में 867.82 रुपये तक लुढ़क गया था।

बुधवार के कारोबार के लिये रिलायंस इंडस्ट्रीज का अधिकतम प्राइस बैंड 2169 रुपये और निम्नतम 1774.90 रुपये तय किया गया था। कारोबार के दौरान आज रिलायंस का शेयर बीएसई में नीचे में 1960 रुपये तक गिरने के बाद सत्र की समाप्ति पर 32.25 रुपये अर्थात 1.64 प्रतिशत की छंलाग से पहली बार दो हजार रुपये के ऊपर 2004 ।10 रुपये पर बंद हुआ। शेयर बाजार में हालांकि आज दिन बाद 37871.52 अंक पर 58.82 अंक अर्थात 0.16 प्रतिशत की गिरावट रही। कारोबार की समाप्ति पर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 1270480.06 लाख करोड रुपये था।

एनएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का भाव 2004 रुपये पर 32 ।45 रुपये अर्थात 1.65 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। रिलायंस का आंशिक भुगतान वाले राईट इश्यू के शेयर का भाव आज 2.2 प्रतिशत बढ़कर 1106.6 रुपये और इसका बाजार पूंजीकरण 46765 करोड रुपये रहा और इसे मिलाकर कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण फिर 13 लाख करोड रुपये को पार कर 1317245 लाख करोड रुपये हो गया।

कोविड-19 संकट से निपटने में भारतीय कारोबार जगत ने दिखाई उच्च स्तरीय तत्परता : एचएसबीसी रपट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस जैसे संकटकाल में भी अधिकतर कारोबारियों ने बड़ी तत्परता से काम लिया। वैश्विक वित्तीय इकाई एचएसबीसी की एक रपट के मुताबिक कोविड-19 के अच्छे-खासे असर के बावजूद कई भारतीय कारोबार सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, वहीं भविष्य के लिए उन्होंने आकस्मिक योजनाएं भी बनायी है। एचएसबीसी 'बिल्डिंग बैंक बैटर' रपट के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल करीब 46 प्रतिशत भारतीय कारोबारों ने माना कि कोरोना वायरस महामारी का उन पर 'गहरा बुरा असर' हुआ है। वहीं 54 प्रतिशत का मानना है कि वह इस तरह के संकट के लिए उतने ही अच्छे तरीके से तैयार थे जितना हो सकते थे। रपट में कहा गया है कि भारतीय कारोबारों का यह लचीलापन विश्व में दूसरे स्थान पर है। वहीं 54 प्रतिशत का यह आंकड़ा सर्वेक्षण में शामिल विभिन्न बाजारों के औसत 45 प्रतिशत अधिक है। एचएसबीसी ने दुनिया के 14 प्रमुख बाजारों में करीब 2,600 कंपनियों के बीच यह सर्वेक्षण किया। इसमें भारत की 200 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। रपट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के काफी नकारात्मक असर का सामना करने के बावजूद करीब 29 प्रतिशत कंपनियों ने माना कि वह सामान्य दिनों की तरह ही परिचालन कर रहे हैं। इस तरह का भरोसा रखने वालों में भी दुनिया के अन्य बाजारों में भारत का स्थान दूसरा है। केवल चीन इन मामलों में पहले स्थान पर है।

शेयर बाजार में नए निवेशकों की भरमार, जान लें SEBI की सलाह

नई दिल्ली। एजेंसी

शेयर बाजार रेकॉर्ड प्रदर्शन कर रहा है। निफ्टी चार महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ इकॉनमी की हालत खराब है। ज्यादातर लोगों का यह सवाल है कि शेयर मार्केट में इतना उछाल क्यों है जब इकॉनमी की हालत इतनी खराब है। इस बीच एँईं ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान शेयर बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है।

लॉकडाउन में खूब आए नए निवेशक

SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि लॉकडाउन के दौरान डीमैट खातों की संख्या में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। इसकी वजह बाजार में नए निवेशकों की भागीदारी बढ़ना है। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ माह के दौरान शेयर बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में जोरदार इजाफा हुआ है।' कई विश्लेषकों का कहना है कि इसकी वजह यह है कि इस दौरान निवेशकों के पास निवेश के अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं थे।

शुरुआत में ज्यादा रिस्क से बचें

त्यागी ने नए निवेशकों का स्वागत किया लेकिन एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं नए निवेशकों से इतना कहना चाहूंगा कि वे शुरुआत में ज्यादा रिस्क नहीं लें। उनके लिए बेहतर होगा कि रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज के साथ बाजार में प्रवेश करें। इक्विटी बाजार में निवेश करने से पहले उन्हें हर तरह से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश सुरक्षित है।

मार्च के झटकों से बाजार ऊबर चुका है

उन्होंने कहा कि बाजार काफी हद तक मार्च के झटकों से उबर चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद बाजार ने पहली तिमाही में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई है। त्यागी ने कहा कि छह माह के लिए ऐंईं के प्रावधानों को निलंबित किए जाने की वजह से कंपनियां और ऋणदाता समाधान के लिए आईबीसी ढांचे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। त्यागी ने कहा कि इसके अलावा नियामक ने कंपनियों द्वारा धन जुटाने की प्रक्रिया को भी आसान किया है।

लिक्विडिटी के कारण शेयर बाजार में तेजी

शेयर बाजार में तेजी को लेकर जानकारों का कहना है कि पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स ने इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए स्टिमुलस पैकेज लाया है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ी है। शेयर बाजार में तेजी उसी का असर है।

छोटे उद्योगों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे सीबीडीटी और एमएसएमई मंत्रालय

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग जल्द ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बिक्री कारोबार और मूल्यह्रास (्रीजर्मूरदह) से जुड़ी पूरी जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ साझा करना शुरू करेगा। यह जानकारी संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा उनकी आयकर रिटर्न में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुरूप होगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में सोमवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीबीडीटी द्वारा जारी वक्तव्य में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि सहमति ज्ञापन के जरिए आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़ी कुछ सूचनाओं को एमएसएमई मंत्रालय के साथ साझा किया जा सकेगा।

क्या मदद मिलेगी

इस सूचना के आधार पर एमएसएमई मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों की जांच और उनके उचित वर्गीकरण में मदद मिलेगी। सीबीडीटी ने 14 जुलाई के अपने आदेश में आयकर प्रधान महानिदेशक (सिस्टम) को एमएसएमई मंत्रालय के साथ सूचनायें साझा करने का निर्देश दिया है। आयकर कानून की धारा 138 आयकर विभाग को यह अधिकार देती है कि वह करदाताओं के बारे में कोई जानकारी अथवा ब्योरा दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है।

आयकर विभाग कानून की इस धारा के तहत एमएसएमई मंत्रालय को छोटे उद्योगों द्वारा उनकी आयकर रिटर्न (आईटीआर) 3,5 और 6 में दी गई प्लांट एवं मशीनरी के मूल्यह्रास, कारोबार की बिक्री, सकल प्राप्ति और आईटीआर-4 में सकल कारोबार अथवा सकल प्राप्ति की जानकारी को साझा कर सकता है।

कब से होगा लागू

सीबीडीटी के इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सूचना भेजने की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों के बारे में आयकर प्रधान महानिदेशक (सिस्टम) एमएसएमई मंत्रालय के प्राधिकृत प्राधिकरण के साथ आपसी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें आंकड़े हस्तांतरित करने के तरीके, आंकड़ों की गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि सहमति ज्ञापन समझौता उसी दिन से प्रभाव में आ जाएगा जिस दिन इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नांगिया एण्ड कं. एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि पिछले महीने सरकार ने एमएसएमई के लिये नये मानदंडों को अधिसूचित किया है। ये मानदंड उनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश और कारोबार के आधार पर तय किए गए हैं। आयकर विभाग और एमएसएमई मंत्रालय के बीच सूचनाओं के आदान- प्रदान से अब उन्हीं एमएसएमई को नए नियमों के तहत यह (एमएसएमई का) दर्जा मिलेगा जिनके आईटीआर में उनके संयंत्र एवं मशीनरी और कारोबार की तय मानकों के अनुरूप जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार ने 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की विभिन्न श्रेणियों के लिये नई परिभाषा तय की।

क्या है संशोधित परिभाषा

संशोधित परिभाषा के मुताबिक प्लांट और मशीनरी में एक करोड रुपये तक निवेश और पांच करोड़ रुपये तक का बिक्री कारोबार करने वाली इकाई 'सूक्ष्म उद्यम' की श्रेणी में आएगी। इसी प्रकार प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश जिनमें हुआ है और उनका कारोबार 50 करोड़ रुपये के दायरे में हैं, उन्हें 'लघु उद्यम' कहा जाएगा। वहीं जिन उद्यमों के प्लांट एवं मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश हुआ है और सालाना कारोबार 250 करोड़ रुपये तक है उन्हें 'मध्यम उद्यम' की श्रेणी में रखा गया है।

ईपीएफओ 'रोजगार': मई में रिकार्ड 3.18 नये पंजीकण

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास मई महीने के अंत तक पंजीकृत अंशधारकों की संख्या में शुद्ध रूप से 3.18 लाख की वृद्धि हुई जो अप्रैल की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है। यह दौर कोराना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू सार्वजनिक पाबंदियों का था जिसमें अब ढील दी जा रही है। ईपीएफओ के वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक आंकड़े संगठित क्षेत्र में रोजगार की दिशा के बारे में जानकारी देते हैं। पिछले महीने जारी अस्थायी आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से 1.33 लाख नए पंजीकरण हुए थे। अप्रैल के इस आंकड़े को संशोधित कर 1,00,825 किया गया है।मार्च में यह आंकड़ा 5.72 लाख और फरवरी में 10.21 लाख था। ईपीएफओ अंशधारकों की औसत मासिक शुद्ध वृद्धि करीब 7 लाख के आसपास रहता है।सोमवार को जारी ईपीएफओ के ताजा आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान शुद्ध रूप से नये अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी। ईपीएफओ अप्रैल 2018 से नये अंशधारकों के आंकड़े जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 से आंकड़े लिए गए हैं। आंकड़े से यह भी पता चलता है कि सितंबर 2017 से मई 2020 के दौरान शुद्ध रूप से जुड़े नये अंशधारकों की संख्या 1.59 करोड़ रही।

डीजीएफटी ने पीपीई किट निर्यात के लिये मंजूरी प्रक्रिया को संशोधित किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिये पूरे शरीर को ढकने को लेकर पीपीई किट के निर्यात हेतु आवेदन देने और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया और मानदंडों में संशोधन किया है। सोमवार को जारी एक व्यापार नोटिस में यह कहा गया है किजुलाई में निर्यातकों ने जो भी अनुरोध दिये, वे अयोग्य पाये गये। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कोविड-19 के इलाज को लेकर 29 जून को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) चिकित्सा किट (कवर ऑल) के निर्यात की अनुमति दी थी। इसमें मासिक निर्यात कोटा 50 लाख इकाई रखा गया था। डीजीएफटी ने कहा, ''एक जुलाई से तीन जुलाई के बीच प्राप्त सभी आवेदनों पर गौर किया गया और काई भी आवेदन 29 जून को जारी व्यापार नोटिस में दिये गये मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अतः सभी आवेदनों को निर्यात कोटा के आबंटन के लिये पात्र नहीं पाया गया है।'' विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि निर्यात को लेकर आवेदन पक्रिया और मानदंड को संशोधित किया गया है और निर्यातकों को इन पीपीई किट (कवर ऑल) के निर्यात को लेकर नये सिरेस से ऑनलाइन आवेदन देने के लिये आमंत्रित किया गया है।' निर्यातकों को खरीद आर्डर की प्रति के साथ प्रति आईईसी (आयात निर्यात कोड) आवेदन देना होगा और फिर उस पर विचार किया जाएगा।

कारोबारियों के लिए बड़ी खबर

GST कंपोजिशन स्कीम को लेकर हुआ बड़ा फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

GST Composition एम्पस का फायदा उठाने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने उएऊ कंपोजिशन स्कीम से जुड़े कारोबारियों को राहत दी है। अब ये कारोबारी हर तिमाही के बजाय सालाना रिटर्न भर सकते हैं। वहीं, FY19-20 के लिए सालाना GSTR-4 फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ गई है। सालाना GSTR-4 फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2020 हो गई है। आपको बाता दें कि उएऊ का भुगतान करने वाला कोई भी सर्विस प्रोवाइडर 31 जुलाई तक यह फैसला कर सकता है कि उसे जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कराना है या नहीं। 50 लाख तक का कारोबार करने वाले सभी सर्विस प्रोवाइडर्स जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम में खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 में जीएसटी काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के लिए एलिजिबल सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को 30 अप्रैल 2019 तक कंपोजीशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कराने का विकल्प दिया था।अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने के बाद उन सर्विस प्रोवाइडर को 6 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। बता दें कि जीएसटी के तहत ज्यादातर सर्विसेज पर 12 फीसदी और 18 फीसदी का टैक्स लगता है। पहले मैन्यूफैक्चरर के लिए थी कम्पोजिशन स्कीम- सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने सर्कुलर में कहा कि ऐसे सप्लायर जो कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें फॉर्म जीएसटी CMP-02 भरना होगा। उन्हें यह फॉर्म 31 जुलाई, 2019 तक भरना होगा। इससे पहले CBIC ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल,2019 तय की थी। जीएसटी कंपोजीशन स्कीम अब तक सिर्फ उन व्यापारियों और मैन्यूफैक्चर्रस को उपलब्ध थी जिनका सालाना कारोबार एक करोड़ रुपये तक है। इस सीमा को एक अप्रैल से बढ़ाकर 1।5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ई-कॉमर्स कंपनियों बताना ही होगा उत्पादों का कंट्री ऑफ ओरिजिन

नई दिल्ली। एजेंसी

ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म में बिक रही आयतित वस्तुओं में उस देश का नाम लिखा हो जहां से उन्हें मंगाया गया है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने हर उत्पाद पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी उत्पाद कहां बना है, इसका जिक्र करना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम और नियमों के तहत ई-कॉमर्स साइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किसी उत्पाद के मूल देश का नाम दर्शाया गया हो।

केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय दिगपॉल के जरिये दायर हलफनामे में कहा गया है कि इन नियमनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है। दिगपॉल ने कहा कि जहां भी इन नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के विधिक मापविज्ञान विभाग के अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हलफनामे में कहा गया है कि इस पर आवश्यक परामर्श सभी ई-कॉमर्स कंपनियों, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विधिक मापविज्ञान नियंत्रकों को भेजा गया है। केंद्र की ओर से यह हलफनामा एक जनहित याचिका पर दायर किया गया है। अधिवक्ता अमित शुक्ला की ओर से दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की आग्रह किया गया था कि ई-कॉमर्स मंचों पर बिकने वाले उत्पादों पर उनका (उत्पादों) विनिर्माण करने वाले देशों का नाम दर्शाया जाना चाहिए।

बता दें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताने के लिए डेडलाइन 1 अगस्त तय कर दिया है। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियां इसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त मांग रही हैं। नए नियमों के तहत पोर्टल पर मौजूद सभी प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूरी है। नई लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम पहले से लागू है।

कंपनियों के सामने ये है दिक्कत

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के नए फीचर लागू होने से पहले जिन सेलर्स ने अपने उत्पाद अपलोड किए हुए हैं, उनको भी कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करना होगा। सरकार उन्हें लगातार रिमाइंडर भेजेगी और इसके बाद भी प्रोडक्ट पर जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। दरअसल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। बैठक में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बदलाव पहले नए उत्पाद लिस्टिंग के लिए किए जाएं क्योंकि उनके प्लेटफार्मों पर पहले से ही बेच रहे लाखों उत्पादों के लिए ऐसा करना मुश्किल है।

सूत्रों के मुताबिक अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रस्ताव को निष्पादित करने के लिए तीन महीने की समयसीमा का अनुरोध किया। अमेजन ने कहा कि उसके लाखों विक्रेता हैं, और हर उत्पाद के लिए 'मूल देश' का उल्लेख करने के लिए उन्हें आश्वस्त करना मुश्किल होगा। इसके लिए तीन महीने की समय मिलना चाहिए। फ्लिपकार्ट ने भी कहा कि इसे विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने और अपने तकनीकी मंच को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है।

चीन को एक और झटका

भारत की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने रद्द किए कई बड़े ऑर्डर

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले दिनों में भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को बड़े लेवल पर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब इन ऑर्डर के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं और दूसरे देशों से अधिक कीमत होने के बावजूद ये सारे सामान मंगा रही हैं। इसकी शुरुआत मई से हुई है जब से पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। इस महीने पावर गियर के आयात पर लगे तमाम प्रतिबंधों के चलते इस मुहिम को और बल मिला है, लेकिन इंडस्ट्री ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इसकी वजह से सप्लाई ना रुके। Indian Electrical & Electronics Manufacturers Association यानी IEEMA के प्रेसिडेंट आरके चुघ ने कहा कि अब तक इंडस्ट्री में कच्चा माल, असेंबली का सामान और काफी सारी बना बनाया सामान भी चीन से ही मंगाया जाता था। IEEMA के डायरेक्टर जनरल सुनील मिश्रा ने कहा कि इंडस्ट्री अब विकल्प की तलाश कर रही है, ताकि चीन से सामान की सप्लाई को रोका जा सके। आरके चुघ ने आगे कहा- 'जब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक इन सामान के लिए भरोसेमंद और दोस्ताना रवैये वाले देशों जैसे जापान, ताइवान, कोरिया और जर्मनी की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर का आयात यूरोप से किया जा सकता है और तमाम कच्चे माल के लिए रूस, चेक रिपब्लिक या पोलैंड का रुख किया जा सकता है। हमारे सदस्यों ने मांग के लिए अन्य देशों का रुख करना भी शुरू कर दिया है।'

निजी ट्रेन पर पहली बैठकः बॉम्बार्डियर, जीएमआर, राइट्स, भेल सहित 16 कंपनियां हुईं शामिल

नई दिल्ली। एजेंसी

151 ट्रेनों के आलाव कुछ और ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के पूर्व सोमवार को आयोजित बैठक में 16 कंपनियों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों में बॉम्बार्डियर, स्पेन की सीएएफ, हवाई अड्डा कंपनी जीएमआर, भारतीय रेल की कंपनी राइट्स और सार्वजनिक उपक्रम भेल भी शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर निजी यात्री रेलगाड़ियां परिचालित की जाएंगी जिससे भारतीय रेल परिवहन क्षेत्र में नई तकनीक आने के साथ साथ भारतीय रेल के राजस्व में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये 151 निजी रेलगाड़ियां उन रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी जो पहले से चल रही हैं। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में संभावित आवेदकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई और रेल मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा आरएफक्यू और बोली प्रक्रिया के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया।

12 निजी कंपनियों से योग्यता के आधार पर आवेदन आमंत्रित

संभावित आवेदकों से प्राप्त प्रश्नों के बारे में रेल मंत्रालय 31 जुलाई, 2020 तक लिखित उत्तर देगा। दूसरा आवेदन पूर्व सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को निर्धारित है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में लगभग 16 संभावित आवेदकों के भाग लेने से उत्साहनजक प्रतिक्रिया मिली। रेल मंत्रालय ने 109 मूल गंतव्य मार्गों पर जोड़ी यात्री रेल सेवाओं के संचालन के लिए 151 आधुनिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए 12 निजी कंपनियों से योग्यता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए की गई पहल है। इस परियोजना के माध्यम से निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। उम्मीद है कि यात्री रेल परिचालन में कई परिचालकों के आने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा जिससे सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। यह पहल यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में भी मदद करेगी।

ढुलाई शुल्क में निश्चितता आएगी

प्रस्तावित परियोजना के लिए निजी कंपनियों का चयन दो चरणों वाली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अनुरोध के लिए अर्हता (आरएफक्यू) और अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) शामिल हैं। बैठक में ढुलाई भाड़े पर भी सवाल किए गए, जिसपर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया की कि ढुलाई भाड़े को अग्रिम रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा और पूरी रियायत अवधि के लिए उपयुक्त रूप से अनुक्रमित किया जाएगा, जिससे ढुलाई शुल्क में निश्चितता आएगी। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि परियोजना के तहत संचालित की जाने वाली गाड़ियों को निजी संस्थाओं द्वारा लीज पर खरीदा या लिया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रेनों के संचालन के संबंध में पक्षों को समान रूप से जोखिम की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

ऋण की किस्त के भुगतान पर रोक समाप्त होने के बाद बैंकों के लिए पूंजी का संरक्षण महत्वपूर्ण : रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 31 अगस्त को ऋण के किस्त के भुगतान पर रोक की अवधि समाप्त होने के कारण बैंकों के लिए पूंजी का संरक्षण और पुनर्पूंजीकरण महत्वपूर्ण होगा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण या पूंजी संरक्षण का विकल्प देने की जरूरत है क्योंकि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों को एक साल तक निलंबित रखने के चलते दबाव वाले खातों का समाधान प्रभावित होगा। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट 'इकोरैप' में कहा, "समस्या यह है कि आईबीसी को एक साल के लिए निलंबित रखने से इस दौरान समाधान नहीं हो सकता है, और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में या तो पूंजी डाली जाए या उन्हें पूंजी संरक्षण का विकल्प दिया जाए, क्योंकि यह साफ नहीं है कि पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के पास कितनी राजकोषीय गुंजाइश है।" इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कोरोना वायरस के प्रकोप से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर बनाने के लिए अग्रिम आधार पर पूंजी जुटाने की जरूरत है। रिपोर्ट में बासेल नियमों में राहत देने की बात भी कही गई, जिससे बैंकों को करीब एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मिल सकती है।

जूम बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा

बेंगलुरु। एजेंसी

जूम वीडियो कम्युनिकेशंस ने कहा कि वह भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी और अगले कुछ वर्षों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा जूम को बड़े स्तर पर अपनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया, "जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच भारत में जूम के मुफ्त उपयोगकर्ता साइन अप में 6,700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" कंपनी ने कहा कि उसका एक कार्यालय पहले ही मुंबई में है और वहां दो डेटा केंद्र हैं।

कंपनी ने आगे बताया कि बेंगलुरु में विस्तार से उसके मौजूदा अनुसंधान और विकास केंद्रों को मदद मिलेगी। जूम ने कहा कि असाधारण इंजीनियरिंग और आईटी प्रतिभा के कारण उसने बेंगलुरु का चयन किया और जल्द ही वह इंजीनियरों, आईटी, सुरक्षा और कारोबार परिचालन क्षेत्र के पेशेवरों को नियुक्त करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि जब तक कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं होता है, उसके कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। कंपनी ने कहा, "जूम के लिए भारत रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है और हमें यहां निरंतर वृद्धि और निवेश करने की उम्मीद है।" जूम के सीईओ एरिक एस युआन ने कहा, "हम भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 2,300 से अधिक शिक्षण संस्थानों में मुफ्त में अपनी सेवाएं देकर गर्व महसूस कर रहे हैं और भारत के लोगों तथा सरकार के साथ काम जारी रखने के लिए तत्पर हैं।" उन्होंने कहा, "हम अगले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए प्रमुख कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें भारत की उच्च-शिक्षित इंजीनियरिंग प्रतिभा को शामिल किया जाएगा।"

भारत, अमेरिका को मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत की मेज पर बैठने की जरूरत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और अमेरिका को एक ''त्वरित व्यापार समझौते को पूरा करने के बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के रूप में एक अधिक टिकाऊ, मजबूत और दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम करने के लिए बातचीत की मेज पर बैठने की जरूरत है। ये बातें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कही। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एफटीए के लिए भारत खुले दिमाग से काम करने का इच्छुक है। भारत बाजारों को खुला रखने की इच्छा के साथ भारतीय व्यवसायियों के लिए भी अमेरिका में बेहतर अवसर चाहता है।

गोयल ने कहा, ''मेरा विश्वास है कि हम पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे बीच उभरे लंबित मामलों को लेकर एक त्वरित व्यापार समझौता कर सकते हैं। इन मामलों को हमें जल्द सुलझाना लेना चाहिए। हम काफी कुछ इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और मेरा मानना है कि अगली कुछ बातचीत में हम इन्हें सुलझा लेंगे। वाणिज्य मंत्री ने कहा, ''इसके बाद जैसा की अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया गया है, अमेरिका और भारत को बातचीत की मेज पर बैठना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह अमेरिका में चुनाव से पहले हो सकता है या फिर चुनाव के बाद, लेकिन हमें एफटीए के रूप में एक अधिक टिकाऊ, अधिक मजबूत और दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम करने की जरूरत है।

समझौते में 50 से लेकर 100 उत्पादों और सेवाएं हो सकती हैं शामिल

गोयल ने कहा कि दोनों देशों को एक तरजीही व्यापार समझौते के बारे में भी विचार करना चाहिए।

इस समझौते में 50 से लेकर 100 उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। तरजीही व्यापार समझौते के तहत दो व्यापारिक भागीदारी सीमित संख्या की वस्तुओं पर आयात शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं या फिर काफी कम कर देते हैं जबकि एफटीए के तहत दोनों देश एक दूसरे के बीच होने वाले व्यापार में अधिक से अधिक उत्पादों पर शुल्क को समाप्त कर देते हैं। भारत और अमेरिका एक सीमित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को और बढ़ावा मिल सके।

क्या चाहता है अमेरिका

भारत, अमेरिका में उसके इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाये जाने वाले ऊंचे आयात शुल्क में छूट दिएजाने, सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) के तहत निर्यात लाभ को बहाल किए जाने और भारत के कृषि, वाहन, वाहन कलपुर्जे और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए अमेरिका के बाजारों में अधिक पहुंच दिएजाने की मांग कर रहा है।वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत में कृषि और विनिर्मित उत्पादों के लिए बाजारों को और अधिक खोला जाए। उसके डेयरी उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों को बेहतर बाजार पहुंच मिले। इसके साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क कम किया जाए। अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर भी चिंता व्यक्त कर चुका है। अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष 2019- 20 में भारत का शीर्ष कारोबारी भागीदार बना हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019- 20 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88।75 अरब डालर का रहा जबकि 2018- 19 में यह 87।96 अरब डालर रहा था।

यूएवी पर भी दोनों देशों के बीच वार्ता

भारत और अमेरिका सीधे हवा में छोड़े जाने वाले मानवरहित यान के साझा उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा अधिग्रहण परिषद के अवर सचिव एलन एम लॉर्ड ने कहा कि वायुसेना, डीआरडीओ और भारत की एक स्टार्टअप कंपनी के साथ यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यूएस-इंडिया बिजनेस काउंस की इंडिया आइडियाज समिट को ऑनलाइन संबोधित करते हुए लॉर्ड ने यह बात कही।

दूरसंचार कंपनियों को थोक ग्राहकों के परिसर के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिएः डॉट

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार विभाग (डॉट) के एक आदेश के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को अब नए कनेक्शन जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन के दौरान थोक ग्राहकों के परिसर के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि एक पोर्टल के जरिए दूरसंचार कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिक्री केंद्र का कोड मुहैया कराना होगा। डॉट ने 20 जुलाई के एक आदेश में दूरसंचार परिचालकों से कहा है कि वे उन सभी मौजूदा कनेक्शन के उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएएफ) में उस सभी अस्पष्ट संदेश को हटाएं या उसे ठीक करें जो ग्राहकों को डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के दौरान दिए गए थे। दूरसंचार विभाग ने आपने आदेश में कहा है, ''थोक ग्राहकों के लिए नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के मामले में, उनके परिसर के भौतिक सत्यापन के दौरान, ग्राहक के परिसर का अक्षांश/ देशांतर और डेटा और निरीक्षण के समय को दर्ज किया जाएगा और उसे सीएएफ और डेटाबेस में दर्ज किए जाए।'' डॉट के इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा थोक कनेक्शन के दौरान सभी ग्राहकों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

होने लगी हैं भर्तियां, इन सेक्टरों में मिल रही हैं बंपर नौकरियां

बेंगलूरु। एजेंसी

कोरोना महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं जिसका रोजगार पर भी गहरा असर हुआ था। लेकिन अब इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। देश में 21 सेक्टरों की 800 से भी अधिक कंपनियों पर नजर रखने वाली स्टाफिंग फर्म टीमलीज के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिक्रूटमेंट सेंटीमेंट में सुधार आया है। अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए हायरिंग इंटेंट 18 फीसदी हो गया है जो 25 मार्च से 7 जून तक लॉकडाउन के दौरान 11 फीसदी था। हायरिंग इंटेट ऐसे नियोक्ताओं का प्रतिशत है जो इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। बेंगलूरु में हायरिंग इंटेंट सबसे अधिक 21 फीसदी है। दिल्ली में 19, हैदराबाद में 15, चंडीगढ़ में 14, कोलकाता और मुंबई में 12 फीसदी है।

बाकी देशों से बेहतर स्थिति

इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि

अमेरिका (8 फीसदी), यूरोप (9 फीसदी) और मध्यपूर्व (11 फीसदी) की तुलना में भारत में स्थिति काफी बेहतर है। हालांकि यह कोरोना से पहले के स्तर के बहुत कम है लेकिन इसमें सुधार इस बात का संकेत है कि देश की इकनॉमी पटरी पर आ रही है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान यह 96 फीसदी था।

इन सेक्टरों में बढ़ी हायरिंग एक्टिविटीज

टीमलीज की को-फाउंडर और ईवीपी रितुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा कि अगर बड़े शहरों में लॉकडाउन नहीं हुआ तो इस वित्त वर्ष की बाकी अवधि के दौरान हायरिंग इंटेट के लगातार बढ़ने की उम्मीद है। देश में रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज में तेजी दिखने लगी है। हेल्थकेयर एंड फार्मास्यूटिक्ल, एजुकेशन सर्विसेज, ई-कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर एंड एग्रो-केमिकल्स, आईटी और एफएमसीजी सेक्टरों में रिक्रूटमेंट की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। इन सेक्टरों में सभी स्तरों पर लोगों को भर्ती करने की योजना है। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जैसी गिग-इकनॉमी से जुड़ी नौकरियों के लिए बेंगलूरु जैसे शहर में आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है। चक्रवर्ती ने कहा कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में हायरिंग एक्टिविटीज में और तेजी आएगी। धीरे-धीरे इसके रफ्तार जोर पकड़ेगी।

सोना-चांदी ने रचा इतिहास, गोल्ड 50000 तो चांदी 60000 के पार

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश भर के सर्राफा बाजारों में आज सोने-चंदी की कीमतों में आग लगी हुई है। आज यानी बुधवार सुबह 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 50220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। यह मंगलावार के मुकाबले 780 रुपये तेज है। वहीं चांदी ने मंगलवार की तरह ही बड़ी छलांग लगाई है। आज चांदी 5193 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 60043 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। वहीं अगर भारतीय वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों की बात करें तो आज दोनो धातुएं नई ऊंचाई पर हैं। चांदी का भाव 60,000 रुपये प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार गया, जबकि सोना भी 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को तोड़ने के करीब है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates~com) के मुताबिक 22 जुलाई 2020 को देशभर के सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे।

क्यों बढ़ रहे सोने-चांदी के दाम

जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इससे शेयर बाजारों में जहां अनिश्चितता का माहौल है वहीं रियल एस्टेट भी पस्त पड़ा है। इस दौर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित सोना ही नजर आ रहा है। निवेशकों का रुझान गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोनावायरस संक्रमण के कारण खनन कार्य प्रभावित होने और आपूर्ति बाधित होने से चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी देखी जा रही है।

बेहतर रिटर्न की गारंटी बना सोना

साल 2001 के बाद से सोने ने प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में सोना 142 फीसद रिटर्न दे चुका है। वहीं पिछले 15 वर्षों में तो सोने ने प्रतिवर्ष 14.7 प्रतिशत का लाभ दिया है। पिछले 10 वर्षों में सोने ने प्रहर साल 10.1 प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष

12.8 प्रतिशत का लाभ दिया है। वहीं दो साल में सोने ने 55% रिटर्न दिया, पिछले छह महीने में ही 24% तक बढ़ इसकी कीमत बढ़ चुकी है।

कौन खरीद रहा सोना

शेयर बाजार में गिरावट और अर्थव्यवस्था में संकट के दौर में तमाम फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना सेफ हैवन इन्वेस्टमेंट यानी सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। केंद्रीय बैंक, फंड मैनेजर्स, स्वतंत्र निवेशक आदि ये सभी लोग पूरी दुनिया में अलग अलग एक्सचेंज पर सोने की खरीदारी कर रहे हैं । सोने के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड उंचाई पर है। इसी वजह से भारत में सोने में तेजी देखने को मिल रही है।

सस्ता कब होगा

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जबतक कोरोना का संक्रमण दुनिया भर के देशों में बढ़ता रहेगा तब तक सोने की कीमतें कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर केडिया कहते हैं कि सोने के दाम तभी गिरेंगे जब मार्केट में कोई कोरोना की वैक्सीन आ जाए और वह सफल भी हो। इसके अलावा भारत और चीन सोना नहीं खरीदते हैं तो दाम कुछ कम हो सकते हैं। फिर भी सोना 44000 से नीचे नहीं जाएगा।

ईश्वर के समीप बैठना ही है उपासना

उपासना का अर्थ पूजा-अर्चना और निराहार रह कर व्रत-साधना करना भर नहीं है। उपासना का वास्तविक अर्थ ईश्वर का सामीप्य पाना है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक, दोनों रूपों में साधना करनी होगी, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी

आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए न तो सही मार्ग जानते हैं और न उस पर चलने के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिशा से भटके प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? आज की यह सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्म विज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न ही उसे किया जाने का तरीका और उसके साधन विधान ही भ्रांतिहीन है। इस उलझन में एक सत्य के जिज्ञासु को निराशा ही मिलती है।

हमें यहां अध्यात्म के मौलिक सिद्धान्तों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना है। इसी कड़ी में साधना के बाद उपासना है। विविध विधि शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्य इसी प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। शरीर से व्रत, मौन, अस्वाद, ब्रह्मचर्य, तीर्थयात्रा, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, पाठ, बंध, मुद्राएं, नेति, धोति, वस्ति, न्योलि, वज्रोली, कपालभांति जैसे क्रियाकृत्य किए जाते हैं। मानसिक साधनाओं में प्रायः सभी चिंतन परक होती हैं और उनमें कितने ही स्तर के ध्यान करने पड़ते हैं। नादयोग, बिन्दुयोग, लययोग, ऋजुयोग, प्राणयोग, हंसयोग, षट्चक्र वेधन, कुण्डलिनी जागरण जैसे बिना किसी श्रम या उपकरण के किए जाने वाले, मात्र मनोयोग के सहारे सम्पन्न किए जाने वाले सभी कृत्य ध्यान योग की श्रेणी में गिने जाते हैं। स्थूल शरीर से श्रमपरक, सूक्ष्म शरीर से चिंतनपरक उपासनाएं की जाती हैं। कारण शरीर से केवल भावना की पहुंच है। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा का भाव भरा समन्वय 'भक्ति' है। प्रेम सम्वेदना इसी को कहते हैं। यह स्थिति तर्क से ऊपर है। भावनाओं की उमंग भरी लहरें ही अन्तःकरण के मर्मस्थल का स्पर्श कर पाती हैं।

अध्यात्म

आचार्य श्रीराम शर्मा

उपासना क्षेत्र में लोगों की असफलता का कारण यही है कि लोग उसे एकांगी बना देते हैं। उपासनात्मक कर्मकाण्डों को ही सब कुछ मानकर चलने से उसके साथ अन्तःकरण की गहराई तक उसका प्रभाव नहीं होने पाता। उपासना स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों से की जानी चाहिए, उन्हें उपासना के योग्य बनाया जाना चाहिए, तभी उसका समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपासना का अर्थ है- समीपता। ईश्वर और जीव में यों समीपता ही है। जब भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, तब मानवी काया एवं चेतना में भी वे समाए हुए क्यों नहीं होंगे। जो अपने में ओत-प्रोत ही है, वह दूर कैसे? और जो दूर नहीं है उसकी समीपता का क्या अर्थ? इस असमंजस की विवेचना इस प्रकार होती है कि यह समीपता उथली है, गहरी नहीं। माना कि शरीर में हलचलों के रूप में और मन में चिंतन के रूप में विश्वव्यापी चेतना ही काम कर रही है, तो भी स्पष्ट है कि जीव की आस्थाएं एवं आकांक्षाएं दिव्य सत्ता के अनुरूप नहीं हैं। मनुष्यता की सार्थकता तभी है, जब उसका स्वरूप एवं स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठ सके। निम्न योनियों के जीवधारी पेट और प्रजनन के लिए जीते हैं। यदि यही अन्तःस्थिति मनुष्य में बनी रहे तो समझना चाहिए कि कायिक विकास ही हुआ-चेतनात्मक नहीं।

इस दयनीय स्थिति से पीछा छुड़ाने के लिए ईश्वर की समीपता का- उपासना का उपक्रम बनाना पड़ता है। शरीर ठंड से कांप रहा हो तो आग की समीपता से आवश्यक गर्मी प्राप्त की जा सकती है। संगति का- समीपता का प्रभाव सर्वविदित है। चंदन के समीप उगे हुए झाड़-झंखाड़ सुगन्धित हो जाते हैं। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भंडार हैं। उसकी समीपता, उपासना में वैसी ही विशेषताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। टिड्डे हरी घास में रहते हैं तो उनका शरीर हरा रहता है, पर जब वे सूखी घास में रहने लगते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। व्यक्तित्वों का भला-बुरा निर्माण करने में वातावरण की अनन्य भूमिका रहती है।

उपासना क्रिया-कृत्य का अन्तरंग और बहिरंग स्तर का ऐसा 'माहौल' बनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के भावनात्मक स्तर में उत्कृष्टता की वृद्धि होती हो। बहिरंग वातावरण बनाने में पूजा उपासना में प्रयुक्त होने वाली प्रतीक प्रतिमा- उसका सज्जा शृंगार, पूजा उपचार में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, उपकरण आदि का मिला जुला स्वरूप अपना काम करता है। पूजा वेदी के समीप बैठने पर ऐसा लगना चाहिए, मानो किन्हीं असाधारण दिव्य परिस्थितियों में जा पहुंचे हों। सामान्य वातावरण से अलग उपासना कक्ष के वातावरण की परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं, जिनमें बैठने पर उत्कृष्टता की अनुभूति बढ़े।

(सौजन्यः गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज)

गायत्री महिमा

गायत्री हैं धर्म-संस्कृति की गंगोत्री

अथर्ववेद में कहा गया है- ऊं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्तवा व्रजत ब्रह्मलोकम्।।

वेद भगवान कहते हैं- गायत्री माता स्तुति करने वाले भक्त को सर्वप्रथम पवित्र कर ज्ञान देकर द्विजत्व प्रदान करती है, वह आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्मतेज और ब्रह्मलोक प्रदान करने वाली है। इसीलिए गायत्री को हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय सभ्यता-संस्कृति का मूलाधार, मेरुदंड वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता कहा गया है। गायत्री ही प्राणतत्त्व के संरक्षण की मूल शक्ति हैं। परमात्मा की सर्वप्रमुख शक्तिस्रोत का आधार भी गायत्री ही हैं। समस्त ऋषियों, देवताओं की उपास्या, आराध्या जगतजननी मां गायत्री ही हैं। गायत्री महाप्रज्ञा हैं। इन्हें ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है। चारों वेदों की जननी, भारतीय धर्म और संस्कृति की उद्गम गायत्री के 24 अक्षरों में वह भावना, शिक्षा और शक्ति निहित है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य लौकिक और पारलौकिक प्रगति की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकता है। इन 24 अक्षरों का गुंथन ऐसे वैज्ञानिक ढंग से हुआ है कि उनका क्रमबद्ध उच्चारण करने मात्र से मनुष्य शरीर में अवस्थित सूक्ष्म चक्र, उपचक्र एवं उपत्यिकाएं जाग्रत होती हैं और गुण, कर्म, स्वभाव में, आत्मिक स्तर में श्रेयस्कर परिवर्तन होता है। फिर यदि भावना एवं विधि-विधान के साथ उनकी उपासना की जा सके, तब तो कहना ही क्या है!

भारत में आदिकाल से ही गायत्री उपासना की प्रधानता रही है। भारतीय धर्म के अनुरूप त्रिकाल संध्या में गायत्री के बिना संध्या उपासना हो ही नहीं सकती। अवतारों, ऋषियों और महापुरुषों ने भी गायत्री की उपासना की है। राम और कृष्ण गायत्री के अनन्य उपासक थे। समस्त ऋषियों की तपश्चर्या का केंद्रबिंदु गायत्री थीं। वैदिक काल में उपासना जगत में गायत्री माता की अत्यंत प्रतिष्ठा थी। इसी के सहारे यहां के निवासियों ने आध्यात्मिक और भौतिक सद्परिणाम भी प्राप्त किए थे।

आत्मबल ही संसार का सबसे बड़ा बल है। उत्थान का मूल स्त्रोत भौतिक साधन-सामग्री में नहीं, आत्मिक स्तर में छिपा हुआ है और हमारी वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रगति का वास्तविक आधार गायत्री महामंत्र के आधार पर विकसित हुआ महान आत्मबल ही हो सकता है। **मुकेष ऋषि**

पौराणिक कथा

...शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाते

दैत्यराज दंभ संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठिन तप कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्रीहरि ने दंभ से वरदान मांगने को कहा। दंभ ने मांगा– प्रभु! मुझे अपने समान तेजस्वी और बलवान पुत्र का वरदान दीजिए, जो तीनों लोकों में अजेय और महापराक्रमी हो। नारायण के आशीर्वाद से दंभ के यहां एक बलशाली पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। आरंभ में शंखचूड़ बहुत धर्मवान था। उसने पुष्कर में जाकर घोर तप किया। ब्रह्माजी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा। शंखचूड ने ब्रह्मदेव से वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्माजी ने शंखचूड़ को इच्छित वरदान के साथ-साथ नारायण कवच भी प्रदान किया।

शंखचूड़ का विवाह धर्मध्वज की परम तेजस्वी और साध्वी कन्या तुलसी से हुआ। शंखचूड का जन्म श्रीहरि के आशीर्वाद से हुआ था। ब्रह्मा से उसने वरदान लिया था। यह सोचकर शंखचूड़ में अभिमान आ गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्रीहरि ने कहा- मैंने स्वयं दंभ को अपने समान परम बलशाली पुत्र का वरदान दिया है। इसलिए शंखचूड़ के अत्याचारों से महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। देवताओं ने महादेव को जाकर अपना कष्ट सुनाया। महादेव देवताओं के दुख दूर करने को तैयार हो गए। महादेव व शंखचूड़ के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। शंखचूड़ के पास नारायण कवच था। इसके साथ-साथ उसकी पत्नी वृंदा ने, जिनका नाम तुलसी भी है, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंखचूड़ को एक अभेद्य कवच से युक्त कर दिया था। इस कारण महादेव उसका वध नहीं कर पा रहे थे।

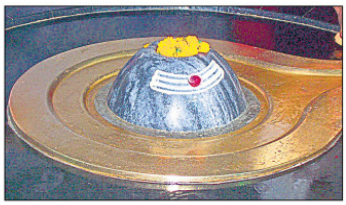

देवताओं ने श्रीहरि से शंखचूड़ के वध की राह निकालने की प्रार्थना की। शंखचूड़ बड़ा दानी भी था। वह प्रतिदिन दान किया करता था। श्रीविष्णु ब्राह्मण रूप बनाकर शंखचूड़ के पास गए और नारायण कवच दान में ले लिया। उसके बाद श्रीहरि ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। अनेक वर्ष के बाद पति को लौटा देख तुलसी प्रसन्न हुईं और पत्नी समान आचरण किया। तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। इसके खंडित होते ही कवच भंग हो गया। महादेव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कहते हैं कि त्रिशूल के प्रहार से नारायण के समान बलशाली शंखचूड़ की हड्डियां चूर हुईं, तो उससे शंख बना।

चतुर्भुज नारायण अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं। इसलिए श्रीहरि एवं अन्य देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु महादेव ने उसका वध किया था, इसलिए उनका शंख से जलाभिषेक करना निषिद्ध है। गजानन भी शिवपुत्र हैं, इसलिए उन्हें भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। **राजन प्रकाश**

मुंबई और दिल्ली में 5जी ट्रायल के लिए तैयार रिलायंस जियो! मांगा स्पेक्ट्रम

नई दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस जियो ने 5उ टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की मांग की है । इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई और दिल्ली में 5 जी का ट्रायल करेगी।

मांगे हैं ये खास स्पेक्ट्रम

कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडिसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5उ सॉल्यूशंस बेचना शुरू कर दिया है । न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5जी के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से 17 जुलाई को स्पेक्ट्रम के लिए अनुरोध किया था । कंपनी ने 26 गीगाहट्र्ज और 24 गीगाहट्र्ज बैंड में 800 मेगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी और 3 ।5 गीगाहट्र्ज बैंड में 100 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की मांग की है।

हाई फ्रेक्वेंसी की जरूरत क्यों

सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है । कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए । सरकार सुझाव और ट्रायल के लिए तैयार है । पहले से ही कई ट्रायल चल रहे हैं।

जियो ने 26.5-29.5 गीगाहट्र्ज और 24.25-27.5 गीगाहट्र्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के बीच स्पेक्ट्रम की मांग की है। इन हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने पिछले साल नवंबर में 26 गीगाहट्र्ज को 5जी स्टैंडर्ड के लिए मंजूरी दी थी, जबकि दूसरे बैंडों के लिए स्टैंडर्ड अभी तय नहीं किया गया है। हाल में अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है। इससे जियो प्लेटफॉर्म्स को 5उ प्लान पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी के पास 5जी टेक्नोलॉजी से जुड़ी विशेषज्ञता है।

मुकेश अंबानी ने किया था ऐलान

हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो ने पूरी तरह स्वदेशी 5जी सॉल्यूशन विकसित किया है । इससे कंपनी देश में विश्वस्तरीय 5जी सर्विस शुरू करेगी। उन्होंने कहा था, 'इससे हम भारत में वर्ल्ड क्लास 5उ सर्विस शुरू कर पाएंगे। जैसे ही स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा, यह मेड इन इंडिया 5उ समाधान ट्रायल के लिए तैयार होगा और इसे अगले साल फील्ड में उतारा जा सकेगा।

गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने दी चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने यूरोपियन यूनियन को चीनी एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। सरकार ने ईयू को चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए 10 हजार टन कोटा निर्धारित किया है। यह कोटा एक अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2021 तक के लिए निर्धारित किया गया है। यानी इस दौरान चीनी का एक्सपोर्ट किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन को रॉ या व्हाइट शुगर के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत कहा गया है कि एक्सपोर्ट करने का जो निर्धारित किया गया है उसे एक अक्टूबर 2020 से शुरू कर सकते हैं और 30 नवंबर 2021 तक इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इसलिए राहत की खबर कही जा सकती है क्योंकि चीनी मिलों के पास काफी ज्यादा सरप्लस चीनी पड़ा हुआ है और ये चीनी सरप्लस होने की वजह से चीनी कंपनियों एक्सपोर्ट करने की मांग कर रही है। चीनी कंपनियों की बाकी मांग अभी सरकार के विचाराधीन है कि एक्सपोर्ट कोटा और एक्सपोर्ट सब्सिडी के तहत कितनी चीनी के एक्सपोर्ट के मंजूरी देनी है। इससे पहले भी सरकार चीनी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडी को मंजूरी देती रही है। फिलहाल राहत की बात ये है कि सरकार ने चीनी कंपनियों को ईयू के लिए चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है।

चीनी शेयरों में तेजी

ईयू को चीनी एक्सपोर्ट की छूट दिए जाने की खबर से शेयर बाजार में चीनी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। धामपुर शुगर, बलरामपुर शुगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उगर शुगर, डामिया भारत के शेयरों में 5 फीसदी तक उछाल दर्ज की गई।

सस्ते विदेशी तेलों का आयात बढ़ने से घरेलू तेल उद्योग पर संकट

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेशों से सस्ते भाव पर खाद्यतेलों का आयात बढ़ने से बुधवार को देशी तेलों की मांग और कमजोर हुई है तथा सोयाबीन डीगम जैसे तेलों की भी मांग प्रभावित हुई है। बाकी तेल तिलहनों के भाव या तो पूर्वस्तर पर बंद हुए या उनमें मामूली गिरावट आई। दूसरी ओर लॉकडाऊन में ढील के बाद स्थानीय व्यावसायिक मांग बढ़ने से पाम तेल कीमतों में सुधार आया। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि मंडियों में अलग भाव पर पामतेल की बिक्री हुई। सूत्रों को आशंका है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि बाजार में कुछ सीपीओ में परिस्कृत पामोलीन का सम्मिश्रण चल रहा है। सस्ते पामतेल की आयात बढ़ने से सोयाबीन डीगम की भी मांग कमजोर रही और सोयाबीन तेल कीमतों में हानि दर्ज हुई। सूत्रों ने बताया कि संभावित रूप से सम्मिश्रण वाले कच्चा पामतेल (सीपीओ) का भाव राजधानी की मंडियों में अधिक यानी 7,360 रुपये क्विन्टल तथा बगैर मिलावट वाले सीपीओ का भाव 7,290 रुपये क्विन्टल है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात की जांच करानी चाहिये और प्रतिबंधित पामोलीन मिश्रित सीपीओ के आयातक कंपनियों का लाइसेंस रद्द करना चाहिये। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय मांग होने के बावजूद सस्ते आयात के बढ़ने के कारण वायदा और हाजिर मंडियों में सूरजमुखी, सोयाबीन दाना जैसे तिलहनों के भाव लागत से भी कम हैं जिससे तिलहन उत्पादक किसान, तेल उद्योग संकट में हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिकी, साथी देशों में रक्षा प्रौद्योगिकी पर बड़े तालमेल की जरूरत:लाल

वाशिंगटन। एजेंसी

भारतीय-अमेरिकी कार्यकारी अधिकारियों के मंच से जुड़े अमेरिकी रक्षा उत्पादन क्षेत्र के एक शीर्ष कार्यकारी ने विवेक लाल ने कहा है कि एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच सामूहिक रक्षा औद्योगिक केंद्रों के साथ एक "अभूतपूर्व तालमेल" की आवश्यकता होगी। इससे उनके साजो सामान की प्रौद्योगिकी जल्दी पुरानी नहीं पड़ेगी। अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) द्वारा आयोजित 'इंडिया आइडियाज समिट' में जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी लाल ने कहा कि वैश्विक रक्षा उद्योग नयी नयी तकनीकों को तेजी से अपना रहा है और ऐसे में चलन से बाहर होने के नुकसान से बचने के लिए सरकारों और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थानांतरित हों या न हों, लेकिन एशिया हमेशा वैश्विक व्यापार के केंद्र में रहेगा। जकार्ता में जन्मे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज्यादातर आर्थिक संकेतक व्यापार के प्रवाह, शुद्ध निवेश प्रवाह और वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रोत्साहित करते रहेंगे, जो मानव विकास और महामारी के बाद सुधार के लिए जरूरी है। दुनिया का लगभग दो-तिहाई तेल लदान हिंद महासागर से प्रशांत महासागर होकर जाता है। दुनिया के 10 सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों में आठ इस क्षेत्र में हैं। वैश्विक व्यापार का तीस प्रतिशत हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है, जिसमें से हर साल 1200 अरब डॉलर की खेप सिर्फ अमेरिका को जाती है। अमेरिकी रक्षा उद्योग की प्रमुख हस्ति लाल ने कहा, "इन सब की सुरक्षा करना पूरे क्षेत्र और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर निर्भर करता है।" लाल ने कहा कि यह उत्साहजनक है कि अमेरिकी सरकार और उसके साथ देश पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के जोखिमों को पहचानते हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के देश समझ रहे हैं कि क्या दांव पर है और वे उसके अनुसार जवाब दे रहे हैं, जापान से लेकर कोरिया तक, ताइवान से ऑस्ट्रेलिया तक, और निश्चित रूप से भारत भी। इसमें एक उद्योग के रूप में हमारी सार्थक भूमिका है।"

Consumer Protection Act 2019

सिनेमा हॉल-होटल में खाने-पीने की वस्तुओं पर वसूले ज्यादा पैसे तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब उपभोक्ताओं को कई अधिकार मिल गए हैं, जो पिछले कानून में नहीं थे। अब सामान खरीदने से पहले भी ग्राहक सामान की शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया पर अगर भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार किया तो कंपनी और विज्ञापन करने वाले दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। अगर अपराध गंभीर है और उससे किसी के जान-माल का नुकसान होता है तो आईपीसी के तहत भी मुकदमे चलेंगे। इस कानून की खास बात यह है कि अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूले गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

MRP से ज्यादा पैसे वसूलने पर होगी कार्रवाई

उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए कानून के बारे में कहा, 'नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 उपभक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। नए कानून में जुर्माना के साथ-साथ सख्त सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। यह कानून उपभोक्ताओं के हाथ को काफी मजबूत करेगा। इस कानून के आ जाने के बाद अब देश में अगले 50 सालों तक कोई नया कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून के आने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर अब तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना-

इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा। इसके साथ-साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा और त्वरित गति से उसका निपटारा करेगा। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे-लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार-प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए। इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का। इसका नेतृत्व महानिदेशक सीसीपीए करेंगे।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कैसे करेगी काम

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन- इस आयोग का काम है कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत सीडीआरसी सुनेगी और फैसला सुनाएगी।

- सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर मिलती है शिकायत तो होगी कार्रवाई।
- खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान।
- कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे।
- नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।
- कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस
- PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था।
- नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई।
- कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत।
- स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये।

कोरोना महामारी के दौर में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए

एचसीसीबी ने अपनी फैक्ट्रियों में लागू किये कई अनूठा नियम

कर्मचारियों के प्रतिदिन के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए की एक एप की शुरुआत

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर लम्बे समय से जारी लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है । इसका मतलब यह कतई नहीं कि संक्रमण खत्म हो गया है, बल्कि अब तो इससे बचाव करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है । लेकिन रोजगार की दृष्टि और वस्तुओं की बाजार में पूर्ती के लिए उद्योगों का काम करना भी आवश्यक है । इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करते हुए काम करने की । इस बात की गंभीरता को भारत की अग्रणी एफएमसीजी कंपनियों में से एक 'हिन्दुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस' (एचसीसीबी) ने बखूबी समझा है । अपने अनूठे और समझदारी भरे उपायों से कम्पनी अपनी फैक्ट्रियों में काम काज को पूरी तरह सुरक्षित बनाया है । कम्पनी ने अपनी फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के छोटे छोटे स्वतंत्र समूह बनाकर काम करने की रणनीति को लागू किया है, ताकि कर्मचारियों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके । इस व्यवस्था को इस तरह लागू किया गया है कि व्यक्तियों के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने का खतरा भी कम से कम हो और यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आता भी है तो उसकी तुरंत पहचान कर उसे आइसोलेट किया जा सके । इन छोटे समूहों को बहुत सावधानी के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि हर समूह के पास सभी आवश्यक साधन रहें, ताकि उन्हें दूसरे समूह के किसी भी व्यक्ति से सम्पर्क करने की आवश्यकता न रहे । यह कदम उन अनेक यूनिक ठोस कदमों में से एक है जो सुरक्षा नियमों को लागू करने के विचार के साथ कम्पनी द्वारा उठाये गये हैं । ताकि देश में 15 स्थानों पर मौजूद फैक्ट्रियों के हर एक कर्मचारी तथा कार्य से जुड़े अन्य सहयोगियों की पूर्ण सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके ।

अपने सुरक्षा मापदंडों/नियमों के अंतर्गत कम्पनी ने अपनी फैक्ट्रियों का विस्तृत रिस्क असेसमेंट किया है, और उन हॉट स्पॉट्स की पहचान की है जहाँ व्यक्तियों के किसी गतिविधि विशेष के लिए आमने-सामने होने की आवश्यकता होती है । कम्पनी ने अपने उन ऑफिस स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी मुहैया करवाई है जिन्हें फैक्ट्रियों में मौजूद रहकर ही काम करने की आवश्यकता नहीं होती। सावधानी को और अधिक सुनिश्चित करते हुए कम्पनी ने काम की संरचना और वर्क फ्लो को फिर से इस तरह तैयार किया है कि अतिसंवेदनशील स्थानों पर लोगों के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने की स्थिति को कम से कम किया जा सके । इसी कड़ी में सभी फैक्ट्रियों के गेट्स पर उपस्थित सिक्योरिटी स्टाफ के लिए विशेष क्यूबिकल्स बनाये गए हैं । यह कवर किया गया स्थान सुरक्षाकर्मियों के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है और उन्हें फैक्ट्री में आने वाले हर व्यक्ति से बिना सम्पर्क में आये उनका तापमान आदि लेने में मदद करता है । कम्पनी ने सभी हॉट स्पॉट्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे फेस शील्ड्स तथा हैण्ड ग्लव्ज़ पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन सबके साथ ही एचसीसीबी ने जनरल शिफ्ट्स तथाजरूरत पड़ने पर रिवाइज़्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी) को खत्म कर दिया है,कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अलग अलग समय निर्धारित कर दिया है, निजी या दफ्तर के वाहनों पर लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक ही स्थान से आने-जाने के कारण लोगों के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने का ख़तरा कम से कम हो इसके लिए फैक्ट्री में आने-जाने के लिए अलग-अलग गेट निश्चित कर दिए गए हैं । पूरे फैक्ट्री प्रांगण को अच्छी तरह साफ़ करने और पूरी तरह निरंतर सैनेटाइज करने के अलावा कम्पनी ने फैक्ट्री के भीतर कई जगहों पर जमीन पर स्पष्ट लिखावट में फ्लोर साइनेज (चेतावनी संकेत) भी लगाए हैं ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने में मदद मिल सके । संवेदनशील प्रोसेसिंग क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए कड़े सेनेटाइज़िंग प्रोटोकॉल्स लागू करने के साथ ही एचसीसीबी ने सभी फैक्ट्रियों में दरवाजों के हैंडल्स फुट पैडल्स और डोर स्टेप्स का प्रावधान रखा है ताकि जर्म्स से किसी भी प्रकार के सम्पर्क में आने की संभावना न रहे। एचसीसीबी ने अपने कर्मचारियों को नियमित अपने स्वास्थ्य संबंधी अपडेट प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हुए एक एप की सुविधा भी प्रदान की है । यह एप कर्मचारियों को स्थिति के अनुसार कोविड-19 संबंधी सभी पॉलिसीज़ और सुरक्षा मापदंडों के बारे में निरंतर सूचित करता रहता है । इन नियमों और उपायों के अलावा एचसीसीबी ने फैक्ट्री के प्रांगण में आने वाले हर वाहन को रोगाणुनाशक के स्प्रे से सैनेटाइज़ करने की सुविधा भी मुहैया करवाई है । साथ ही हर फैक्ट्री में विशेष आइसोलेशन रूम स्थापित किये गए हैं ताकि किसी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नजर आने पर उसे शासकीय प्रोटोकॉल के अनुसार बाकी लोगों से अलग रखा जा सके । कम्पनी ने काम संबंधी किसी भी यात्रा को न करने या फैक्ट्री के भीतर किसी भी व्यक्ति, सहकर्मी या विजिटर से मीटिंग न करने को लेकर स्पष्ट और कड़क गाइडलाइंस जारी की हैं । यही कारण है कि वर्तमान में कम्पनी अपनी फैक्ट्रियों में शासन अनुमोदित क्षमता और मैन पावर से भी कम के साथ कार्य संचालन कर रही है, ताकि लोगों को एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से रोका जा सके ।

HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PVT. LTD.

516 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए काफी

मुंबई। एजेंसी

देश में रिकार्ड स्तर पर पहुंचे 516 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार से और अधिक विदेशी मुद्रा प्रवाह आकर्षित करने के साथ ही कंपनियों के लिए विदेशी कोष की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की गई है। बैंक आफ अमेरिका की मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के पद संभालने के बाद से ही विदेशी मुद्रा भंडार में 81 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है।

516 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार

शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर कार्यभार संभाला था। उनके बैंक के गवर्नर रहते विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। उनके प्रयासों के चलते बिमल जालान, वाई वी रेड्डी जैसे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नरों का समय याद आ गया। उनके समय में पहली बार देश का आरक्षित कोष आयात को पूरा करने लायक पर्याप्त स्तर पर पहुंचा था। देश का 516 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार करीब 15 महीने की आयात जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 20 प्रतिशत तक है। वहीं कोरोना से पहले 11।4 महीने के आयात लायक कवर उपलब्ध था।

हालांकि, अधिक माह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त होना काफी कुछ कच्चे तेल के घटे दाम की वजह से भी संभव हुआ है। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार से चालू खाता यथावत रह सकता है। हालांकि, यह स्थिति तब होगी जब वर्ष के दौरान कच्चे तेल का औसत दाम 43।7 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक देश के शेयर बाजारों में वर्ष के दौरान सात अरब डॉलर की राशि डालें। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020- 21 के दौरान रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में 45 अरब डॉलर का हस्तक्षेप कर सकता है, जिसमें से रिजर्व बैंक 25।5 अरब डॉलर का अब तक पहले ही कर चुका है। इससे पहले 2019-20 में रिजर्वबैंक ने 45 अरब डॉलर बाजार में डालकर रुपये को बचाया है।

भारत में 1000 रुपये हो सकती है कोरोना वैक्सीन की कीमत

मुंबई। एजेंसी

भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन करने जा रहे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, इसलिए हम इसकी कीमत कम से कम रखेंगे। उन्होंने इस पर शुरुआत में प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में इसकी कीमत 1000 रुपये के आसपास या इससे कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। इसलिए वैक्सीन की मांग बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में हमें उसके उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकारी मशीनरी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रयोगात्मक कोविड -19 वैक्सीन को बनाने के लिए बायोफर्मासिटिकल कंपनी AstraZeneca के साथ पार्टनरशिप की है। पूनावाला ने कहा कि वे कोविड -19 वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत अगस्त के अंत तक 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों से की जाएगी। आवश्यक नोड्स प्राप्त करने के बाद अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर होगा वैक्सीन का प्रोडक्शन-हम बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और इस हफ्ते वैक्सीन के लिए मंजूरी लेने जा रहे हैं। पूनावाला ने बताया कि दिसंबर तक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 30-40 करोड़ डोज बनाने में हम सफल हो जाएंगे ।

'मधु' के चक्कर में दो कंपनियों में छिड़ी जंग

बेंगलुरु। एजेंसी

मधु यानी शहद को लेकर इन दिनों डाबर और मेरिको कंपनी के बीच जंग छिड़ी हुई है। डाबर ने आरोप लगाया है कि मेरिको ने उसकी नकल कर के ही अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। मेरिको ने शहद के बिजनेस में पिछले ही महीने एंट्री की है और अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पिछले ही हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश में ये बात भी कही गई थी कि दोनों ही कंपनियों को प्रोडक्ट काफी हद तक एक जैसे लग रहे हैं, जिसकी वजह से खरीददा के मन में कनफ्यूजन पैदा हो सकता है, भले ही बॉटल पर सफोला लिखा हुआ है। अभी तो कोर्ट ने डाबर को एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए राहत दी है और कहा है ये निषेधाज्ञा उन प्रोडक्ट पर लागू नहीं होगी जो पहले ही मेरिको की तरफ से बेचे जा चुके हैं। हालांकि, अभी दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि 17 जुलाई के कोर्ट के आदेश के मुताबिक मामला कोर्ट में ही है। डाबर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। मेरिको ने भी कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वह शहद की मैन्युफैक्चरिंग और बेचना करना जारी रखेगा। डाबर पैकेज्ड शहद 1965 से बेच रहा है, जिसने केस में कहा है कि ट्रेड ड्रेस, लेबल, पैकेजिंग, गेट सब मेरिको ने डाबर की नकल की है। खासकर बोतल की कैप, रंग और लेबल। पिछले वित्त वर्ष में शहद का करीब 482 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।